

**DIPLOMA IN PARALEGAL PRACTICE
(DIPP)**

Term-End Examination

00420

June, 2015

BLE-004 : RURAL LOCAL SELF GOVERNANCE

Time : 3 hours

Maximum Marks : 100

PART A

Answer any two of the following questions in about 600 words each. Each question carries 20 marks. 2×20=40

1. Analyse the serious limitations operating on the working of Panchayati Raj Institutions (PRIs) created by the 73rd Constitutional Amendment.
2. Explain in detail the Micro Finance Institutions functioning in India and the existing regulations governing them.
3. Discuss the schemes and initiatives introduced by the Government of India in order to achieve the National Health Policy Goals.
4. Discuss the basic steps involved in the land acquisition process.

PART B

Answer any four of the following questions in about 300 words each. Each question carries 10 marks. 4×10=40

5. Discuss the common powers and functions assigned to Gram Sabhas in different States.
6. Enunciate the important powers, authorities and responsibilities cast upon the Panchayats under the Eleventh Schedule of the Constitution of India.
7. Analyse the effects and impact of Disasters.
8. Discuss the interpretation given by the Supreme Court of India on the 'Right to Food' in the case of PUCL vs. Union of India and others W.P.(Civil) 196 of 2001.
9. Highlight the Rulings of Supreme Court of India on the issue "Right to Housing" in the following cases :
 - (a) Olga Tellis vs. Bombay Municipal Corporation (AIR 1986 SC 180)
 - (b) Chameli Singh vs. State of UP (1996) 2 SCC 549 (132).
10. Discuss the important types and categories of land laws with the help of examples.

PART C

*Write short notes on any **four** of the following in about 150 words each. Each note carries 5 marks. 4×5=20*

- 11. Audit of Panchayat Accounts**
 - 12. Procedure for instituting a Civil Case under Gram Nyayalaya Act, 2008**
 - 13. Unemployment Allowance under NREGA**
 - 14. Human Right to Water : International framework**
 - 15. The Rights vested upon the Forest Dwellers, Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers under the Forest Rights Act, 2006**
 - 16. Legal Aid and the Role of Paralegals**
-

अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा
(डी.आई.पी.पी.)
सत्रांत परीक्षा
जून, 2015

बी.एल.ई.-004 : ग्रामीण स्थानीय स्वशासन

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

भाग क

निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। $2 \times 20 = 40$

1. 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तुत पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण सम्बन्धी गंभीर सीमाओं (प्रतिबंधों) का विश्लेषण कीजिए।
2. भारत में लघु वित्त संस्थाओं की कार्यप्रणाली और उन्हें शासित करने वाले मौजूदा विनियमों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं और पहलों की चर्चा कीजिए।
4. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में सम्मिलित मूलभूत चरणों की चर्चा कीजिए।

भाग ख

निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। 4×10=40

5. विभिन्न राज्यों में ग्राम सभाओं को सौंपी गई सामान्य शक्तियों और कार्यों की चर्चा कीजिए।
6. भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को प्रदान की गई महत्वपूर्ण शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए।
7. आपदाओं के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
8. PUCL बनाम भारत संघ और अन्य W.P. (Civil) 196 of 2001 के मामले में 'भोजन के अधिकार' पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या की चर्चा कीजिए।
9. निम्नलिखित मामलों में "आवास के अधिकार" के मुद्दे पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर प्रकाश डालिए :
 - (क) ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (AIR 1986 SC 180)
 - (ख) चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) 2 SCC 549 (132)
10. उदाहरणों की सहायता से भूमि-विधियों के महत्वपूर्ण प्रकारों और श्रेणियों की चर्चा कीजिए।

भाग ग

निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लगभग 150 शब्दों (प्रत्येक) में लिखिए। प्रत्येक टिप्पणी 5 अंकों की है। $4 \times 5 = 20$

11. पंचायत के लेखाओं की लेखा-परीक्षा
 12. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत सिविल मामला दायर करने के लिए प्रक्रिया
 13. नरेगा के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता
 14. जल सम्बन्धी मानव अधिकार : अंतर्राष्ट्रीय संरचना
 15. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन निवासियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के निहित अधिकार
 16. कानूनी सहायता और अर्धविधिकों की भूमिका
-